मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

फ़रीदाबाद में मज़दूर पिस रहे हैं 2
पठान फिल्म का विरोध करने आये गुंडों को भगाया 4
वीएचपी ने 2002 के दंगों में मुसलमानों के सफाए की योजना बनायी थी 5
आखिर वांगचुक क्यों - 40 डिग्री तापमान में 5 दिन का करेंगे उपवास ? 6
'बीके हॉस्पिटल' में भ्रष्टाचार की थाह पाना संभव नहीं 8

वर्ष 37 | अंक 11 | फरीदाबाद | 29 जनवरी-4 फरवरी 2023 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

गुंडागर्दी के बल पर एसआरएस मॉल पर कब्जा

फरीदाबाद (म.मो.) सेक्टर 31 स्थित एसआरएस टावर में बने मॉल में 22 जनवरी को यकायक 50-60 युवक घुस आये, सबके हाथ में लाठी-डंडे वगैरा थे। इन्होंने मॉल के मेंटेनेंस दफ्तर पर कब्जा कर लिया। वहां मौजूद स्टाफ़ को मार-पीट कर भगा दिया तथा कुछ को बंदी बना लिया। निकट ही स्थित थाना सेक्टर 31 व अन्य पुलिस अधिकारियों को फोन लगाये गये लेकिन किसी ने भी मौके पर पहुंच कर कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई करते भी कैसे जब तक इलाके के बादशाह एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर का आदेश न मिले। मॉल पर कब्जा करने वाला यह गिरोह इन्हीं मंत्री महोदय से आज्ञा लेकर कब्जा करने आया था।

इस गुंडा गिरोह का नेतृत्व वही अमर चेची कर रहा था जिसका नाम पिछले दिनों पुलिस विभाग द्वारा जारी दलालों की सूची में प्रमुख था। इसे कृष्णपाल का भांजा बताया जाता है। मौके पर तो पुलिस ने क्या पहुंचना था, थाने में शिकायत करने पहुंचे पीड़ित प्रवेश व उनके सहयोगियों की भी कोई सुनवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि हमलावरों ने गैस कटर से लोहे का दरवाजा काटकर उनके लैपटॉप, कम्प्यूटर, हार्डडिस्क, सीसी कैमरों की डीबीआर तथा चेकबुक भी कब्जे में ले ली है। उन्होंने धमकी दी है कि टावर के आस-पास भी दिखे तो जान से मार देंगे।

दरअसल इस तरह के मॉल हों अथवा रिहायशी सोसायटियां, इन सब में मेंटेनेंस के नाम पर लूट कमाई का एक बड़ा धंधा राजनेताओं व प्रशासन के संरक्षण में चलता है। किसी भी बिल्डर की तरह एसआरएस वालों ने भी जेल जाने से पहले लूट का यह ठेका अपने चहेतों को दे रखा था। उनके जेल जाने के बाद मंत्री कृष्णपाल से स्वीकृति पाकर संदीप चपराना ने यह ठेका छीन लिया था। उसका सहयोगी था राजेश भारद्वाज। उस समय अमर चेची भी संदीप चपराना के साथ था। कुछ समय बाद इन दोनों में जबरदस्त टकराव हुआ जिसके कारण अमर चेची संदीप का यह रोजगार छीनने की फिराक में था। अब मौका एवं मंत्री की स्वीकृति पाकर चेची ने चपराना का यह धंधा छीन लिया।

जब चपराना को यह काम दिया गया था उस वक्त मंत्री के मामा राजपाल की मंथली करीब एक लाख तय की गई थी। मंथली तो बदस्तुर राजपाल को मिल ही रही थी लेकिन अब सवाल आ गया अमर चेची का। ऐसे में चपराना की जगह प्राथमिकता मिली अमर चेची को। मंत्री से स्वीकृति मिलते ही चेची ने चपराना के तमाम कारिंदों एवं मैनेजरों आदि को मार-पीट कर भगा दिया। यहां मंत्री की स्वीकृति का मतलब यह होता है कि बेखौफ़ गुंडागर्दी करो, कब्जा करो पुलिस उधर झांकेगी भी नहीं। सो वही हुआ भी।

अब चपराना की जगह चेची के आदमी लूट के इस कारोबार को चलायेंगे। यह लूट कोई छोटी-मोटी नहीं, अच्छी-खासी है।

प्रत्येक दुकानदार अथवा दफ्तर चलाने वालों को 15 रुपये प्रति वर्ग-फुट के हिसाब से मेंटेनेंस चार्ज देना होता है। लाखों वर्ग-फुट के इस मॉल से अच्छी मोटी कमाई हो जाती है। इसके अलावा मॉल में खाली पड़ी दुकानों पर भी ये लोग कब्जा करके मोटा किराया डकारते हैं। जाहिर है कि लूट कमाई का ये धंधा राजनेताओं व शासन-प्रशासन की मर्जी के बगैर नहीं चल सकता।

वरिष्ठ आईएएस अशोक खेमका भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं?

फरीदाबाद (म.मो.) अपने अब तक के सेवा काल में 55 तबादलों से सुसज्जित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने मुख्यमंत्री खट्टर को पत्र लिख कर कहा है कि राज्य में चहुं ओर व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने का ठेका उन्हें दिया जाय इसके लिये उन्हें विजिलेंस प्रमुख बनाया जाय।

तरस आता है बेचारे अशोक खेमका की समझ पर जो 36 साल तक हरियाणा सरकार की और आठ साल तक खट्टर की नौकरी करने के बावजूद यह नहीं समझ पाये कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री निकलती कहां से है? जब उन्हें यही नहीं पता तो वे इस गंगोत्री को थामेंगे कैसे? इतना सबक तो उन्हें अपनी उन तैनातियों से ही सीख लेना चाहिये था जिनसे उनको केवल इसलिये भगाया गया कि उन्होंने भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया था।

बतौर परिवहन सचिव अपनी तैनाती के दौरान जब उन्होंने विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का काम शुरू ही किया था तो उन्हें पद से चलता कर दिया गया था। उस वक्त खेमका को यह समझ नहीं आया कि भ्रष्टाचार किसकी छात्रछाया में पनपता है और इससे कौन-कौन लाभान्वित होते हैं? जाहिर है भ्रष्टाचार की इस लूट कमाई से लाभान्वित होने वालों के हाथ में ही राज्य की बागडोर है। मतलब बड़ा स्पष्ट है, जो

अशोक खेमका : मिस्टर ईमानदार

जीअनुपमा : भ्रष्टाचार की मूर्त

रमेश पाल : सेवानिवृत्त डीसीपी

आज तक खेमका की समझ में नहीं आया, खुद मुख्यमंत्री उनका पूरा मंत्रीमंडल एवं विधायक दल की मिलीभगत से ही भ्रष्टाचार एवं लूट-खसूट का कारोबार चल रहा है। चुनाव जीतने के लिये करोड़ों-अरबों रुपये केवल इसलिये खर्च नहीं किये जाते कि सत्तारुढ़ होकर वे जनता की सेवा करेंगे बल्कि इसलिये कि जमकर लूट का मेवा खायेंगे। ऐसे में भला कौन राजनेता खेमका को भ्रष्टाचार बंद करने का ठेका दे सकता है?

अपने पत्र में खेमका ने एक बड़े काम की बात यह बताई कि वे जिस अभिलेखागार विभाग में तैनात हैं वहां करने को कोई काम नहीं है। सप्ताह भर में मात्र एक घंटे से अधिक का काम नहीं है। विभाग का सालाना बजट चार करोड़ का है। जबकि 40 लाख रुपये सालाना तो उन्हें वेतन के रूप में दे दिया जाता है और काम धेले का नहीं लिया जाता। सरकारी धन के दुरुपयोग का यह कोई अकेला मामला नहीं है। धनाभाव का रोना रोनेवाली सरकार इस तरह के अनेकों दुरुपयोग करने में जुटी है। एक अनुमान के अनुसार करीब एक तिहाई आईएएस तथा इतने ही आईपीएस अफ़सरों के लिये सरकार ने ऐसी कई खुड्डा लाइन पोस्ट बना रखी हैं जहां करने को कोई काम नहीं होता। इन पोस्टों पर खेमका जैसे उन अफसरों को बैठा कर रखा जाता है जो भ्रष्टाचार को समाप्त करके भ्रष्टाचारियों के पेट पर लात मारना चाहते हैं। इसके अलावा जो कोई भी अफसर सरकार के इशारे पर नाचने से इनकार करे उन्हें भी इन्हीं खुड्डों में बैठाया जाता है। सरकारी धन के इस दुरुपयोग का सारा बोझ गरीब कर दाता पर पड़ता है।

पेश है खेमका की अक्ल और ईमानदारी का एक नमूना

बात है दिसम्बर सन् 2005 की। एक शिकायतकर्ता ने तत्कालीन डीएसपी विजिलेंस रमेश पाल को शिकायत की कि रहेजा नामक एक आयकर अधिकारी उससे 25 हजार की रिश्वत मांग रहा है। रमेशपाल ने तुरन्त कार्रवाई शुरू करते हुए अपने एक सुरेश कुमार एएसआई को लिखित दरखास्त देकर तत्कालीन उपायुक्त, जी अनुपमा के पास डयूटी मैजिस्ट्रेट लगवाने के लिये भेजा। जी अनुपमा ने एएसआई से पूछा कि रेड किस पर करनी है? एएसआई ने कहा कि उसे नहीं मालूम, पूछना चाहो तो डीएसपी साहब से पूछ लो। उसने यह भी कहा कि दफ्तर में कुछ बिजली वाले भी घूम रहे थे, हो सकता है कि रेड किसी बिजली वाले पर हो। यह सुनकर जी अनुपमा ने सुनीता वर्मा नामक एक एचसीएस अधिकारी को बतौर डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया।

इसी बीच डीएसपी रमेशपाल को पता चला कि केन्द्र सरकार के अधिकारियों पर रेड करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। विजिलेंस मुख्यालय चंडीगढ़ के निर्देश पर उन्होंने केस को ज़िला पुलिस के हवाले कर दिया। इस पर तत्कालीन पुलिस अधिक्षक महेन्द्र सिंह श्योरान ने डीएसपी बदन सिंह राणा को रेड करने का काम सौंप दिया, डयूटी मैजिस्ट्रेट के तौर पर सुनीता वर्मा ही रही। रेड कामयाब रही, भ्रष्ट आयकर अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

इस पूरी कहानी में न तो कहीं डीएसपी रमेशपाल का दोष नजर आता है और न ही उस एएसआई का जो जी अनुपमा के पास दरखास्त लेकर पेश हुआ था। इसके बावजूद जी अनुपमा ने विजिलेंस के दोनों अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत कर दी कि उन्हें यह नहीं बताया गया था कि रेड किस पर होनी है? बड़ी अजीब शिकायत थी। ऐसा कोई कानून नहीं है कि उन्हें बताया ही जाय। यदि फ़िर भी उन्हें जानना ही था तो वे सीधे डीएसपी से बात करती, जो उन्होंने नहीं की। अनुपमा की शिकायत पर एएसआई का तो तुरन्त तबादला कर दिया गया और सारे मामले की जांच का काम श्रीमान अशोक खेमका को सौंप दिया गया। ईमानदारी की इस मूर्ति ने, दुनियां जहान की भ्रष्ट अधिकारी अनुपमा की आधारहीन शिकायत पर डीएसपी रमेशपाल को दोषी घोषित कर दिया।

अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिये रमेशपाल कई वर्षों तक जगह-जगह सिर मारते रहे, तब कहीं जाकर वे निर्दोष तो घोषित हो गये लेकिन सजा के तौर पर रोके गये उनके दो एंक्रिमेंट आज तक भी बहाल नहीं हुए जबकि वे 2018 में सेवा निवृत हो चुके हैं। ऐसी है हरियाणा की अंधी सरकार और उसको चलाने वाले अशोक खेमका व जी अनुपमा जैसे 'ईमानदार' अधिकारी।